भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1305
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

युवाओं के लिए नए रोजगारों का सृजन

1305. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार द्वारा नए रोजगारों के सृजन में कितनी प्रगति हुई है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगारों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान वर्ष के दौरान रोजगार में वृद्धि दशक में सबसे निचले स्तर पर है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने को प्रोत्साहित करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमश: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक सृजित रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

योजनाएं/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार (लाख में)	3.87	5.87	5.33
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	233.74	267.96	265.33
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	0.76	1.38	1.49
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	1.15	1.78	0.44 (27-01-2020 तक)

स्रोतः संबंधित मंत्रालय

(ग एवं घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएओ वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 से आरंभ किया गया है। सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर 2011-12 (एनएसएस 68वां), 2017-18 (पीएलएफएस) और 2018-19 (पीएलएफएस) के दौरान अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमशः 38.6%, 34.7%, 35.3% था।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****